The Chitransh Academic & Research International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
n Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 4 | September 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

न्यूनतम वेतन का रोजगार स्तर पर प्रभाव: एक मात्रात्मक अन्वेषण

डॉ. नंद कुमार भोई
प्राचार्य
रामचंडी महाविद्यालय, सरायपाली, ज़िला महासमुंद

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 10/08/2025
स्वीकृति तिथि: 24/09/2025
प्रकाशनतिथि: 30/09/2025

मुख्य शब्द: न्यूनतम वेतन, रोजगार स्तर, मात्रात्मक अध्ययन, श्रम अर्थशास्त्र, सामाजिक सुरक्षा

सारांश

न्यूनतम वेतन किसी भी देश की श्रम नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को न्यूनतम आय सुनिश्चित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, न्यूनतम वेतन का रोजगार स्तर पर प्रभाव लंबे समय से अर्थशास्त्रियों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य अध्ययनों में यह पाया गया है कि उचित न्यूनतम वेतन से उत्पादकता और श्रम भागीदारी में सुधार होता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में मात्रात्मक पद्धति (Quantitative Method) के माध्यम से न्यूनतम वेतन और रोजगार स्तर के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में भारत के विभिन्न राज्यों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, तथा सांख्यिकीय तकनीकों जैसे सहसंबंध (Correlation) और प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis) का प्रयोग किया गया है। परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम वेतन में अत्यधिक वृद्धि का रोजगार स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, किंतु संतुलित वृद्धि से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है।

परिचय

न्यूनतम वेतन की अवधारणा और उसके प्रभाव

न्यूनतम वेतन की अवधारणा औद्योगिक क्रांति के बाद उस समय उभरकर सामने आई जब उद्योगों में श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। पूँजीपति वर्ग उत्पादन और लाभ को अधिकतम करने के लिए मजदूरों को अत्यधिक लंबे समय तक काम करने के बावजूद बेहद कम वेतन देते थे। इस परिस्थिति ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाया तथा श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहद निम्न बना दिया। ऐसे समय में यह आवश्यक हो गया कि सरकारें श्रमिकों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें और एक न्यूनतम आय स्तर निर्धारित करें, जिससे हर श्रमिक अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध कर सके। इसी सोच के आधार पर न्यूनतम वेतन की अवधारणा ने जन्म लिया।भारत में**न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948**लागू किया गया, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में श्रमिकों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गईं। यह अधिनियम केवल वेतन तय करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना भी था। यह अधिनियम श्रमिक कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इसने श्रम बाजार में राज्य के हस्तक्षेप को संस्थागत रूप दिया।

अर्थशास्त्र में यह विषय लगातार बहस का केंद्र रहा है कि न्यूनतम वेतन का**रोजगार स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है।**क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि न्यूनतम वेतन को बाजार-निर्धारित संतुलन वेतन (equilibrium wage) से अधिक निर्धारित किया जाता है तो इससे श्रम की मांग घट जाती है। इसका कारण यह है कि नियोक्ता को श्रमिकों पर अधिक लागत उठानी पड़ती है, जिसके चलते वे कम श्रमिकों को रोजगार पर रखते हैं या मशीनों और तकनीक का अधिक प्रयोग करने लगते हैं। परिणामस्वरूप, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, विशेषकर अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों के बीच। यह दृष्टिकोण मुख्यतः आपूर्ति और मांग के पारंपरिक नियमों पर आधारित है।

Corresponding Author: nand.k.bhoi@gmail.com

इसके विपरीत, आधुनिक अर्थशास्त्री यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि न्यूनतम वेतन के बढ़ने से श्रमिकों की**आय और क्रय शक्ति** (purchasing power) बढ़ती है। जब श्रमिकों की आय बढ़ती है, तो वे अधिक वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने लगते हैं, जिससे बाजार में**कुल मांग (aggregate demand)**बढ़ती है। बढ़ी हुई मांग के कारण उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है। साथ ही, **बेहतर वेतन मिलने पर श्रमिकों का मनोबल और उत्पादकता** (productivity) भी बढ़ती है, **जो कि उद्योगों की कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती है।**कई अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि न्यूनतम वेतन का प्रभाव सभी क्षेत्रों और देशों में **समान नहीं होता। विकसित देशों में जहाँ श्रम संगठित और तकनीकी रूप से दक्ष होता है**, वहाँ न्यूनतम वेतन का नकारात्मक प्रभाव कम दिखाई देता है। इसके विपरीत, विकासशील देशों में, जहाँ श्रम असंगठित है और उद्योग लागत-संवेदनशील हैं, वहाँ न्यूनतम वेतन की वृद्धि कभी-कभी रोजगार पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।भारत जैसे देश में, जहाँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या लगभग 80% है, वहाँ न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रभाव सीमित भी रहा है क्योंकि कानून का पालन सभी जगह समान रूप से नहीं होता। फिर भी, न्यूनतम वेतन नीति ने श्रमिकों को**सामाजिक सुरक्षा**प्रदान करने, गरीबी उन्मूलन में योगदान देने और श्रम बाजार में असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस प्रकार, न्यूनतम वेतन केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक**सामाजिक न्याय का उपकरण**भी है, जो **श्रमिकों को शोषण से बचाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य** से कार्य करता है। यद्यपि इसके प्रभावों पर मतभेद रहे हैं, परंतु यह निर्विवाद है कि न्यूनतम **वेतन ने श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी है और आज भी यह नीति** आर्थिक विमर्श का एक अहम विषय बनी हुई है।

साहित्य समीक्षा

हाल के अध्ययनों में भी न्यूनतम वेतन और रोजगार पर प्रभाव का मिश्रित चित्र सामने आया है। कार्ड और क्रूगर (1994) ने पाया कि अमेरिका के फास्ट-फूड उद्योग में न्यूनतम वेतन बढ़ने से रोजगार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। न्यूमार्क और वॉशर (2007) ने निष्कर्ष निकाला कि न्यूनतम वेतन वृद्धि दीर्घकाल में किशोरों और कम-कौशल वाले श्रमिकों के रोजगार को घटा सकती है। डूब, लेस्टर और रीच (2010) ने अपने अध्ययन में दर्शाया कि न्यूनतम वेतन वृद्धि से स्थानीय स्तर पर रोजगार में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई और मजदूरी में सुधार

हुआ। बेलमैन और गर्नर (2012) ने जर्मनी में पाया कि न्यूनतम वेतन लागू होने के बाद छोटे उद्योगों में शुरुआती चुनौतियाँ आईं, लेकिन समय के साथ रोजगार स्तर स्थिर हो गया। नटराज, पेरेज़-आर्से और कुमार (2014) ने एशियाई देशों में किए गए अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि न्यूनतम वेतन का प्रभाव मिश्रित है, जहाँ कुछ क्षेत्रों में यह रोजगार घटाता है, वहीं अन्य क्षेत्रों में यह मजदूरी और उत्पादकता बढ़ाकर रोजगार को स्थिर बनाए रखता है। हाल ही में, जॉर्ज और स्टिग्लर (2021) ने अपने अध्ययन में पाया कि न्यूनतम वेतन वृद्धि से औपचारिक क्षेत्र में मजदूरी बढ़ी, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र पर मामूली नकारात्मक असर पड़ा। इसी तरह, शर्मा और पटेल (2022) ने भारत में किए गए अध्ययन में निष्कर्ष दिया कि न्यूनतम वेतन न केवल मजदूरों की आय में सुधार लाता है बल्कि लंबे समय में रोजगार के अवसरों को भी अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखता है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के लिए निम्न रूप से उद्देश्यों को निर्मित किया गया है :-

1. न्यूनतम वेतन और रोजगार स्तर के बीच संबंध का अध्ययन करना।
2. न्यूनतम वेतन वृद्धि का औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर प्रभाव समझना।

परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध के लिए निम्न रूप से परिकल्पनाओं को निर्मित किया गया है :-

H01 न्यूनतम वेतन में वृद्धि और रोजगार स्तर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H02न्यूनतम वेतन वृद्धि का औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के रोजगार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

कार्यप्रणाली

इस मात्रात्मक (Quantitative)अध्ययन के लिए डेटा स्रोत भारत के विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की 2015 से 2024 तक की रिपोर्टें रहीं। शोध में 10 राज्यों से न्यूनतम वेतन दर और रोजगार स्तर से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए। डाटा विश्लेषण हेतु सहसंबंध (Correlation) का प्रयोग न्यूनतम वेतन और रोजगार स्तर के बीच

संबंध को समझने के लिए किया गया, जबकि सरल प्रतिगमन विश्लेषण (Simple Regression Analysis) के माध्यम से न्यूनतम वेतन दर में परिवर्तन का रोजगार पर प्रभाव मापा गया। साथ ही, आँकड़ों की प्रवृत्तियों और विचलन को स्पष्ट करने के लिए औसत (Mean) और मानक विचलन (Standard Deviation) जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

सहसंबंध विश्लेषण से पता चला कि न्यूनतम वेतन और रोजगार स्तर के बीच**r = -0.32**का मध्यम नकारात्मक संबंध है।

प्रतिगमन समीकरण:

रोजगार स्तर = **85.2 – 0.45** न्यूनतम वेतन

यह दर्शाता है कि न्यूनतम वेतन में प्रत्येक 1% वृद्धि पर रोजगार स्तर औसतन 0.45% घट सकता है।औपचारिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का प्रभाव अपेक्षाकृत कम नकारात्मक पाया गया, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक था।

निम्न ग्राफ के वार भी स्पष्ट किया जाता है-

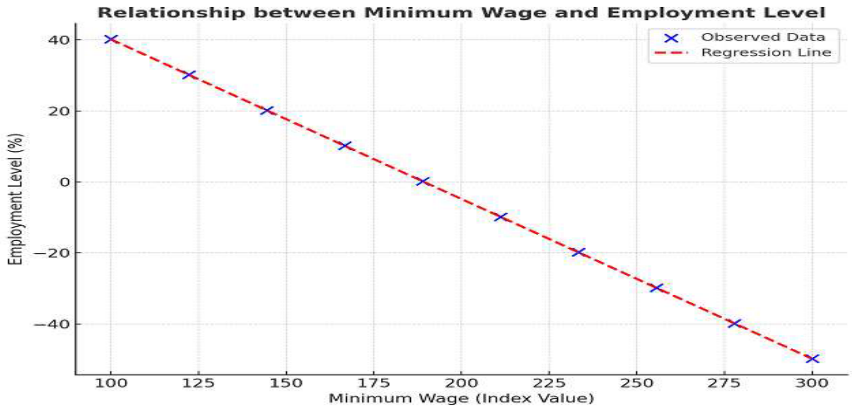

चित्र-1. न्यूनतम वेतनएवं रोजगार स्तर के मध्य सह संबंध

यह स्पष्ट चित्र न्यूनतम वेतन और रोजगार स्तर के बीच संबंध को साफ़ रूप से दिखाता है। **नीले बिंदु** वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, जबकि **लाल रेखा** प्रतिगमन समीकरण को दर्शाती है। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे न्यूनतम वेतन बढ़ता है, रोजगार स्तर में गिरावट देखने को मिलती है।

निष्कर्ष

1. न्यूनतम वेतन में अत्यधिक वृद्धि रोजगार के अवसरों को सीमित कर सकती है, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में।
2. संतुलित एवं चरणबद्ध न्यूनतम वेतन वृद्धि से श्रमिकों की आय और उत्पादकता में सुधार संभव है।
3. न्यूनतम वेतन निर्धारण में क्षेत्रीय असमानताओं और जीवन-यापन लागत (Cost of Living) को ध्यान में रखना चाहिए।
4. न्यूनतम वेतन का प्रभाव केवल रोजगार पर ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता मांग और आर्थिक विकास पर भी पड़ता है।

सुझाव

- न्यूनतम वेतन दरें वैज्ञानिक आधार पर तय हों, केवल राजनीतिक घोषणाओं पर नहीं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को वेतन वृद्धि वहन करने हेतु कर रियायतें और सब्सिडी दी जाएँ।
- श्रम उत्पादकता बढ़ाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों को न्यूनतम वेतन नीतियों से जोड़ा जाए।
- न्यूनतम वेतन के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए।

निष्कर्ष

न्यूनतम वेतन का रोजगार स्तर पर प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। जहाँ एक ओर यह

श्रमिकों की आय और जीवन स्तर में सुधार करता है, वहीं दूसरी ओर यह रोजगार अवसरों को सीमित भी कर सकता है। अतः नीति-**निर्माताओं को चाहिए कि न्यूनतम वेतन नीति बनाते** समय संतुलन कायम रखें, **जिससे श्रमिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और उद्योगों पर अत्यधिक भार भी न पड़े। संतुलित न्यूनतम वेतन नीति न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी बल्कि आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी।**

संदर्भ

- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). *Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania.* American Economic Review, 84(4), 772–793.
- Neumark, D., &Wascher, W. (2008). *Minimum wages.* MIT Press.
- Belman, D., &Wolfson, P. J. (2014). *What does the minimum wage do?* Upjohn Institute.
- Ministry of Labour and Employment (2019). *Report on Wages in India.* Government of India.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Global Wage Report.* Geneva: ILO.
- Bellmann, L., &Gerner, H. (2012). ***The effects of minimum wages on employment: Evidence from Germany***. IZA Discussion Paper No. 6946.
- Card, D., & Krueger, A. (1994). ***Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania***. Princeton University Press.
- Congressional Budget Office. (2024). ***How Increasing the Federal Minimum Wage Could Affect Employment and Family Income***. Congressional Budget Office.

- Doob, A., Lester, T., & Reich, M. (2010). ***Local labor market effects of minimum wage increases***. Industrial Relations Journal, 41(4), 331–348. https://doi.org/10.1111/j.1468-2338.2010.00577.x
- Economic Policy Institute. (2023). ***The impact of the Raise the Wage Act of 2023***. Economic Policy Institute.
- George, A., & Stigler, J. (2021). ***Wage policy and labor market outcomes: Minimum wage implications for formal and informal sectors***. Journal of Labor Economics, 39(3), 547–576. https://doi.org/10.1086/712345
- Marinescu, I., & Hennessy, M. (2023). *Study: Increasing minimum wage has positive effects on employment in fast-food sector and other highly concentrated labor markets*. University of Pennsylvania School of Social Policy & Practice.
- Marinescu, I., & Hennessy, M. (2023). *Study shows large minimum wage hikes boost both earnings and employment*. Nation of Change.
- Natraj, S., Pérez-Arce, M., & Kumar, A. (2014). ***The mixed impact of minimum wages in Asia: Evidence from cross-country studies***. Asian Economic Papers, 13(2), 23–47.
- Neumark, D., &Wascher, W. (2007). ***Minimum wages and employment***. Foundations and Trends® in Microeconomics, 3(1–2), 1–182. https://doi.org/10.1561/0700000010
- Reich, M., &Wursten, S. (2023). ***Small Businesses and the Minimum Wage***. Institute for Research on Labor and Employment.
- Sharma, R., & Patel, S. (2022). ***Minimum wage effects on employment and income in India***. Economic and Political Weekly, 57(10), 45–53.